(e) if so, the date on which first recommendation was sent and the date of the revised list sent;

(f) whether it is a fact that Government propose to reconsider its decision; and

(g) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) to (g) Although recommendations were sought from Ministry of Health and Family Welfare for drugs required under various National Health Programmes, their enlistment finally in Category I was done as per criteria evolved by the Department of Chemical.

Drugs required for Maternal and Child Health Programme are being evaluated for price control recommendations under Category I of the Drug Prices Control Order, 1987 to the Department of Chemicals.

Harmful effects of Khesari Dal

1955. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the harmful effects of the consumption of Khesari dal on the health of the human beings; and

(b) if so, what steps Government propose to take to check consumption of Khesari Dal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) Yes, Sir. The Government is aware of the fact that continuous consumption of Khesari dal as a staple food over a prolonged period may cause lathyrism. Sale of Khesari dal in any form has been prohibited under the provisions of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955. All the States/UTs except Government of Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal have issued ban notification in pursuance of the Rule 44-A of the P.F.A. Rules.

जाली हरिजन प्रमाणपत्रों के जरिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश

1956. **श्री सोहन लाल धूसिया :**

श्री राम चन्द्र विकल :

श्री हरि सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यदि कोई गैर हरिजन अपने को हरिजन कह कर हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे से किसी शैक्षिक या तकनीकी संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर डिग्री हासिल कर ले और बाद में यह सिद्ध हो जाए कि अमुक व्यक्ति हरिजन नहीं है तो क्या सरकार उस व्यक्ति की डिग्री जब्त करके उस पर मुकदमा चलाएगी ; और

(ख) ऐसे मामलों को निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साहो) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों को सामान्यतया, उनके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री इत्यादि को सदा के लिए सही और उपयुक्त कारण से समाप्त करने का अधिकार है । किसी मामले के गुणावगुण के आधार पर कोई विश्वविद्यालय उसके द्वारा प्रदान की गई डिग्री को समाप्त करने पर विचार कर सकता है यदि कोई छात्र अ०ज० और अ०ज०जा० के संबंध में झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके दाखिला प्राप्त करता है जो व्यक्ति जाली/झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है ।